28 May, 2018

Cost of emerging as major military power: $112bn by '27

AGENCIES

NEW DELHI: India's initiatives to bolster its position as a major aerospace and defence power would probably push up its gross defence budget to $112 billion by FY27, Assocham-KPMG joint study revealed on Sunday.

According to the joint study report, this would mean a quantum leap from $45 bn announced by the the government in 2018-19.

The study noted that while the 2018-19 budgetary increase was "a meagre 7.8 per cent over the previous year", it was expected to clock an estimated compound annual growth rate (CAGR) of about 11 per cent until FY27. However, the report raised concerns that about 10 per cent of the defence budget had been surrendered "to Ministry of Defence (MoD) at the end of each financial year owing to underutilisation as the reserved budget is not mapped with capital acquisition". Besides, the report pointed out that the country's capital expenditure for defence

procurement was expected to exceed $250 bn over the next 10 years, primarily to replace the Soviet-era vintage equipment and meet the growing modernisation needs of the country's otherwise mighty armed forces. "However, out of this the domestic industry would only be able to manufacture defence equipment worth just about $80 bn while the rest of it would have to be imported," the report pointed out.

"Thus, the study suggested the government to incentivise private enterprises for developing large scale research and development (R&D) and manufacturing capabilities." The joint study added that "a vibrant domestic manufacturing ecosystem that includes both public and private defence manufacturing entities is essential for success of 'Make in India', in the defence sector".

India's defence budget has already broken into the world's top five, beating the UK for the first time, and signalling a key shift in the military balance between the two countries.

According to a new report by a London-based global think-tank, India overtook the UK as the fifth-largest defence spender in the world in 2017 at $52.5 billion, up from $51.1 billion in 2016. According to the 'Military Balance 2018' report by the International Institute for Strategic Studies (IISS), the UK's defence budget in contrast fell from $52.5 billion in 2016 to $50.7 billion last year.

"This represents a key shift in the military balance between India and the UK, with India allocating more capabilities to develop its regional resources than the UK in a global context," Rahul Roy Chaudhury, IISS Senior Fellow for South Asia, said.

The report noted that while India continued to modernise its military capabilities, China, "with the world's second-largest defence budget after the US" was far ahead with three times India's defence budget at $150.5 bn.

Eastern Chronicle

Punjab Kesari 28 May, 2018

रक्षा बजट बढ़ेगा 112 अरब डॉलर तक

नई दिल्ली, (वार्ता): रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को जोर-शोर से अपनाने के सरकार के प्रयासों से वित्त वर्ष 2027 तक देश के रक्षा बजट के 11 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ वर्तमान के 45 अरब डॉलर से बढ़कर 112 अरब डॉलर पर पहुंचने का अनुमान है।

उद्योग संगठन एसोचैम और बाजार अध्ययन करने वाली एजेंसी केपीएमजी की जारी अध्ययन रिपोर्ट' क्रिएटिंग ए लेवल फील्ड टू फैसिलिटेट मेक इन इंडिया इन डिफेंस' के मुताबिक एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में देश की स्थिति बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों से रक्षा बजट अगले नौ साल में तीन गुणा बढ़ जायेगा। अध्ययन के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन में गत वित्त वर्ष की तुलना में मात्र 7.8 प्रतिशत की बढोतरी की गयी लेकिन वित्त वर्ष 2027 तक यह आवंटन 11 फीसदी की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़गा। अध्ययन में हालांकि इस बात की चिंता भी जाहिर की गयी है कि रक्षा बजट का करीब 10 प्रतिशत हिस्सा हर साल रक्षा मंत्रालय द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। अध्ययन में कहा गया है कि अगले दस साल में रक्षा क्षेत्र की खरीद 250 अरब डॉलर के आंकड़ के पार पहुंचने की उम्मीद है।

- **रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को जोर-शोर से अपनाने पर अगले नौ साल में तीन गुणा बढ़ने की उम्मीद**

ASSOCHAM INDIA

Dainik Navajyoti

28 May, 2018

एसोचैम और केपीएमजी की रिपोर्ट

वर्ष 2027 तक रक्षा बजट 112 अरब डॉलर तक होगा

एजेंसी/नवज्योति, नई दिल्ली

रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को जोर-शोर से अपनाने के सरकार के प्रयासों से वित्त वर्ष 2027 तक देश के रक्षा बजट के 11 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ वर्तमान के 45 अरब डॉलर से बढ़कर 112 अरब डॉलर पर पहुंचने का अनुमान है। उद्योग संगठन एसोचैम और बाजार अध्ययन करने वाली एजेंसी केपीएमजी की आज जारी अध्ययन रिपोर्ट क्रिएटिंग ए लेवल प्लेइंग फील्ड टू फैसिलिटेट मेक इन इंडिया इन डिफेंस के मुताबिक एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में देश की स्थिति बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों से रक्षा बजट अगले दो साल में तीन गुणा बढ़ जाएगा। अध्ययन के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन में गत वित्त वर्ष की तुलना में मात्र 7.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई, लेकिन वित्त वर्ष 2027 तक यह आवंटन 11 फीसदी की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ेगा। अध्ययन में हालांकि इस बात की चिंता भी जाहिर की गई है कि रक्षा बजट का करीब 10 प्रतिशत हिस्सा हर साल रक्षा मंत्रालय द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। अध्ययन में कहा गया है कि अगले दस साल में रक्षा क्षेत्र की खरीद 250 अरब डॉलर के आंकड़े के पार पहुंचने की उम्मीद है। यह राशि मुख्य रूप से सोवियत संघ के जमाने के पुराने उपकरणों को हटाकर उनकी जगह नए अत्याधुनिक उपकरण लेने और भारतीय सेना की बढ़ती जरूरतों की पूर्ति में खर्च की जाएगी। हालांकि, इस राशि में करीब 80 अरब डॉलर के रक्षा उपकरणों की आपूर्ति घरेलू उद्योगों द्वारा की जा सकती है और शेष उपकरणों को आयात करना होगा।

अध्ययन में इस बात पर जोर दिया गया है कि सरकार को वृहद स्तर पर शोध एवं विकास के कार्यों को तवज्जो देने और विनिर्माण गतिविधियों में तेजी लाने के उद्देश्य से निजी कंपनियों को प्रोत्साहन देना चाहिए। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल की सफलता के लिए सरकारी और निजी संस्थानों के अनुकूल घरेलू माहौल तैयार करना होगा। अवसरों की प्रचुर उपलब्धता, तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था और कुशल श्रमबल के होने के बावजूद भारत ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में स्वनिर्भरता की दिशा में सीमित सफलता हासिल की है। रक्षा खरीद प्रक्रिया में कम कीमत के आधार पर निविदा देना, निविदा को रद्द करना और समान अवसर की गैर मौजूदगी जैसी समस्याएं हैं। नामांकन के आधार पर रक्षा क्षेत्र की सरकारी कंपनियों को ऑर्डर देना, डीआरडीओ के तहत अनुमोदन और पूंजी लागत में अंतर के कारण विदेशी कंपनियों और रक्षा क्षेत्र की सरकारी कंपनियों को लाभ होने जैसे मसले भी हैं। एसोचैम के अनुसार सरकार को निजी कंपनियों को उपकरण या सेवा प्रदाता की जगह साझेदार के रूप में देखना चाहिए।

Deshbandhu 28 May, 2018

रिपोर्ट उद्योग संगठन एसोचैम की रिपोर्ट में खुलासा

वर्ष 2027 तक रक्षा बजट 112 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा

नई दिल्ली, 27 मई (एजेंसियां)। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को जोर-शोर से अपनाने के सरकार के प्रयासों से वित्त वर्ष 2027 तक देश के रक्षा बजट के 11 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ वर्तमान के 45 अरब डॉलर से बढ़कर 112 अरब डॉलर पर पहुंचने का अनुमान है। उद्योग संगठन एसोचैम और बाजार अध्ययन करने वाली एजेंसी केपीएमजी की आज जारी अध्ययन रिपोर्ट' क्रिएटिंग ए लेवल फील्ड टू फैसिलिटेट मेक इन इंडिया इन डिफेंस' के मुताबिक एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में देश की स्थिति बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों से रक्षा बजट अगले नौ साल में तीन गुणा बढ़ जाएगा।

अध्ययन के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन में गत वित्त वर्ष की तुलना में मात्र 7.8प्रतिशत की बढोतरी की गयी लेकिन वित्त वर्ष 2027 तक यह आवंटन 11 फीसदी की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ेगा। अध्ययन में हालांकि इस बात की चिंता भी जाहिर की गयी है कि रक्षा बजट का करीब 10 प्रतिशत हिस्सा हर साल रक्षा मंत्रालय द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। अध्ययन में कहा गया है कि अगले दस साल में रक्षा क्षेत्र की खरीद 250 अरब डॉलर के आंकड़े के पार पहुंचने की उम्मीद है। यह राशि मुख्य रूप से सोवियत संघ के जमाने के पुराने उपकरणों को हटाकर उसकी जगह नये अत्याधुनिक उपकरण लेने और भारतीय

कोट-रक्षा क्षेत्र में देश की स्थिति बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाएं जा रहे कदमों से रक्षा बजट अगले नौ साल में तीन गुणा बढ़ जाएगा : एसोचैम

सेना की बढ़ती जरूरतों की पूर्ति में खर्च की जायेंगी। हालांकि, इस राशि में करीब 80 अरब डॉलर के रक्षा उपकरणों की आपूर्ति घरेलू उद्योगों द्वारा की जा सकती है और शेष उपकरणों को आयात करना होगा। अध्ययन में इस बात पर जोर दिया गया है कि सरकार को वृहद स्तर पर शोध एवं विकास के कार्यों को तवज्जो देने और विनिर्माण गतिविधियों में तेजी लाने के उद्देश्य से निजी कंपनियों को प्रोत्साहन देना चाहिए। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल की सफलता के लिए सरकारी और निजी संस्थानों के अनुकूल घरेलू माहौल तैयार करना होगा। अध्ययन में कहा गया है कि अवसरों की प्रचुर उपलब्धतता, तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था और कुशल श्रमबल के होने के बावजूद भारत ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में स्वनिर्भरता की दिशा में सीमित सफलता हासिल की है। रक्षा खरीद प्रक्रिया में कम कीमत के आधार पर निविदा देना, निविदा को रद्द करना और समान अवसर की गैर मौजूदगी जैसी समस्याये हैं।

Divya Himachal 28 May, 2018

2027 तक 112 अरब डालर होगा रक्षा बजट

नई दिल्ली — रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को जोर-शोर से अपनाने के सरकार के प्रयासों से वित्त वर्ष 2027 तक देश के रक्षा बजट के 11 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ वर्तमान के 45 अरब डालर से बढ़कर 112 अरब डालर पर पहुंचने का अनुमान है। उद्योग संगठन एसोचैम और बाजार अध्ययन करने वाली एजेंसी केपीएमजी की आज जारी अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक अगले नौ साल में यह तीन गुणा बढ़ जाएगा।